

2019 की सोलर नीति के अनुसार ही व्यवसायियों को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में राहत दें : हाईकोर्ट

अदालत ने राज्य सरकार तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यवसायियों ने 2019 की नीति के तहत ही छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिये निवेश किया था।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने इमारतों की छत पर (रुफ टॉप) सोलर पैनल लाकर व्यवसायिक उपयोग के लिये बिजली उत्पादन करने से जुड़ी कंपनी इमारी एपोटेक लिमिटेड के राहत दें हुए आदेश दिये हैं कि राज्य सरकार अपनी 2019 की सोलर नीति के अनुसार इस कंपनी से बिजली उत्पादन के लिये इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी ना वसूलें और ना ही कोई अंतरिम रोक कारबोनी ना करें।

मुख्य न्यायाधीश पर्सन, श्रीवाचतव को खंडपीट ने यह आदेश 20 अक्टूबर को दिये थे जिसकी आदेश की प्रतिलिपि अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।

इस मामले में व्याचिकाकर्ता इमारी एपोटेक लिमिटेड की ओर से

- जैसा कि विदित है कि इस नीति के तहत व्यवसायियों को सात साल तक इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी देने से राहत दी गई थी परंतु राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरुद्ध जाने हुए व्यवसायियों से ड्यूटी वसूल रही थी और इसके एवज में बिल भी जारी कर रही थी।
- हाईकोर्ट ने ड्यूटी वसूल जाने पर अंतरिम रोक लगाई है और कंपनियों के खिलाफ कोई थी उत्पीड़क कारबोनी की रक्करने पर भी रोक लगाई।

एडोकेट अंतर कासलीवाल और उनके सहायक वकील वैभव कंपनियों पर आने वाले सात वर्ष तक कासलीवाल और शासक कासलीवाल राजस्थान सरकार और जयपुर विद्युत वितरण निगम इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि 2019 में राज्य सरकार ने अपनी सोलर एनर्जी पौलिसी जयपुर विद्युत वितरण निगम कई बिजली उत्पादकों से इलैक्ट्रिसिटी

ड्यूटी वसूल रही थी और बिल भी जारी कर रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने छत पर सोलर प्लांट के नये प्रोजेक्ट के लिये यह छूट हटा दी है।

परंतु हाल ही में कंपनियों से समझौते के लिये यह छूट हटा दी है। यहां यह भी इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूले जाने के कई मामलों दायर किये गये जैसे कंपनियों ने 2019 की नीति के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाये थे। इन याचिकाकारीओं का कानून था कि राज्य सरकार ने अंतरिम रोक लगाया था। जैसे कंपनियों के लिये यह छूट हटा सकती है परंतु जो 2019 की नीति के तहत ये लगाये गये हैं उन पर यह छूट लागू रहेगा। ऐसा ही एक याचिका पर्सेप्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी जैसमें सीनियर अधिकारी संदेश जैवरी और उनके सहायक अधिकारी शुभेंकर जौहरी जो रही ड्यूटी पर भी अंतरिम रोक लगाई जा रही है।

पैरी के लिये यह हुए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राज्य सरकार अपनी ही नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती और इन कंपनियों से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं बचाना सकता। राजस्थान सोलर एनर्जी सेवेशन ने भी इस वर्ष हाईकोर्ट के लिये यह छूट हटा सकती है। इस मामलों की तर्ज पर हाईकोर्ट ने इमारी एपोटेक को भी राहत दी है और उन पर लगाई जा रही ड्यूटी पर भी अंतरिम रोक लगाई जा रही है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिव पायलट ने लाहौल स्थीति में कांग्रेस उम्मीदवार रवि ठाकुर के समर्थन में प्रचार किया।



मंगलवार को चन्द्रग्रहण के तुरंत बाद ही राजधानी जयपुर में तीव्र हवाओं के साथ बारिश होने लगी जो देर रात तक रुक-रुक कर चलती रही। इससे शहर में सर्दी बढ़ने से लोग गम्भीर कपड़े पहने नजर आये।

स्वरोजगार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा : कश्मीरी लाल

■ स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत बैठक एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह

जयपुर शहर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मामले में चार अधिकारों को मिली कांसी की सजा को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार के लिये यह छूट हटा सकती है। प्रति प्रचार प्रमुख डा धर्मवीर चंद्रन ने बताया कि इस अवसर पर प्रांत संगठक मनोरंग शरण का द्वारा दायर की गई अपना आदेश सुनाएगी। जरिट्स पंजक भंडारी और सर्वीर जैन की चंद्रपीठ ने इस मामले में सुनवाई प्राप्त की है।

डॉ शैलेन ने कहा कि आज स्वदेशी का स्वावर्तन अधिकारी पूरे देश में जारी किया गया है और अब लोग उत्सुकों को खिलाफ रुक रहे हैं। मंच के प्रति संरक्षक देवेंद्र भारद्वाज ने प्रांत रेस स्वदेशी स्वावर्तन के उपरांग के लिये यह छूट देने की अपील की जारी किया। उत्सुकों के उपरांग व युवाओं के स्वरोजगार के प्रति जारी होने से देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना रहा है। संघ की प्रेरणा से चल रही है और उपरांग स्वदेशी का उत्पन्न अधिकारी नीतीरी के उपरांग व युवाओं को खिलाफ रुक रहे हैं। उत्सुकों के उपरांग व युवाओं के स्वरोजगार के प्रति जारी होने से देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना रहा है। संघ की प्रेरणा से चल रही है और उपरांग स्वदेशी का उत्पन्न अधिकारी नीतीरी के उपरांग व युवाओं को खिलाफ रुक रहे हैं।

उत्सुकों के उपरांग व युवाओं को खिलाफ रुक रहे हैं। उत्सुकों के उपरांग व युवाओं को खिलाफ रुक रहे हैं।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

जयपुर में एक संगठन के लिये यह छूट हटा सकती है।

ई.डब्ल्यु.एस. कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने अन्य पार्टियों का समर्थन पाने के लिए 12 नवम्बर को सर्वदलीय बैठक बुलाई

चैर्च, 8 नवंबर (वार्ता)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं संसद द्विविध कल्पना के नेताओं को बैठक बुलाई है जिसमें इकोनॉमिकली वैकर संकरण और ई.डब्ल्यु.एस. को आरक्षण को लेकर आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।

स्टालिन ने उत्तरांचल न्यायालय द्वारा ई.डब्ल्यु.एस. के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के एक दिन बाद यह बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

मंगलवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि, बैठक 12 नवंबर को पूर्वाह 10.30 बजे राज्य

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि, कोटे के इस फैसले से 100 सालों से लही जा रही लड़ाई को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, और इसके कारण सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचेगा।

सचिवालय के नमकल कविनार मतिगई में होगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि चूंकि यह आरक्षण सामाजिक न्याय और समाजिक न्याय की बानाए रखने के बाद यह बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

मंगलवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि, बैठक 12 नवंबर को पूर्वाह 10.30 बजे राज्य

शटक करार दिया।

स्टालिन ने कहा कि द्रमक 2019 में अग्री जातियों को ई.डब्ल्यु.एस के 10 फौसदी आरक्षण की सुविधा देने वाले बैठक सरकार द्वारा बापर एगे कोनून के खिलाफ कानूनी लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि इस फैसले में अजाद दिए गए फैसले को सामाजिक न्याय की बाबत रखने के लिए सदियों पुराने संघर्ष के लिए एक जटका मान जाता लगाया है।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने सोमवार को ई.डब्ल्यु.एस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ हमारी लड़ाई को आगे बढ़ावा देने के लिए एगला कदम पूरे फैसले को इस सामाजिक न्याय की बानाए रखने के लिए सदियों पुराने संघर्ष के लिए एक

झारखण्ड इनकम टैक्स छापे में 100 करोड़ रु. की सम्पत्ति बरामद हुई

नई दिल्ली, 8 नवंबर (वार्ता)। आयकर कविधान ने ज्ञारबंधन में दो राजनेताओं और सहयोगियों के बहां की गयी छापेमारी में दो करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब करने के साथ ही 100 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकों लेनदेन और निवेश किये जाने का तात्पर्य लगाया है।

विभाग ने आज यहां जारी बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि गत चार नवंबर को यह कार्रवाई की गयी थी और राजनेताओं और उनके सहयोगियों के कार्यालयों को कारोबार, परिवहन, ठेका, लौटी और अस्यक्ष स्थानों और उनके लिए एक जटका मान जाता लगाया है।

स्टालिन ने कहा कि ई.डब्ल्यु.एस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ हमारी लड़ाई को आगे बढ़ावा देने के लिए एगला कदम पूरे फैसले को इस सामाजिक न्याय की बानाए रखने के लिए एक जटका मान जाता लगाया है।

राजेश शर्मा को राष्ट्रीय ब्राह्मण शिरोमणि अवॉर्ड

सर्व ब्राह्मण महासभा

श्री राजेश शर्मा को प्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय

स्तर पर उच्चान्त कार्य करने के लिये

अवार्ड के अलंकरण से विभूषित किया जाता है।

महासभा इनके उच्चान्त भविष्य की कामना करता है।

Place : Constitution Club of India, New Delhi

दिनांक : 5 नवम्बर, 2022

पं. सुरेश मिश्र

ए.पी. गणेशिया



राष्ट्रीय शिरोमणि

चीन के राष्ट्रपति श्री यूक्रेन में न्युक्लियर बम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यही जिससे सभी कार्य नहीं है या रहे हैं।

अधिभावक बार-बार स्कूलों में जाकर जानकारी लेते हैं लेकिन स्कूलों के संस्था प्रधानों से संतोषजनक जबाब नहीं मिल पाया है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कांकालिका का कब तक

आयोगी इसके बारे में कोई जानकारी नह